हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

हर खबर पर पैनी नजर

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

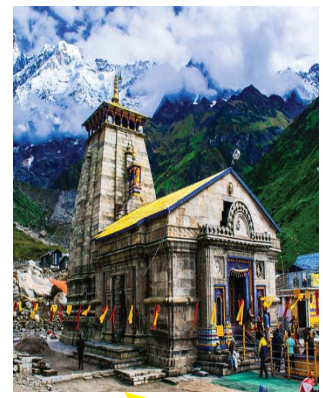

वर्ष:5 अंक:25 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये pathpravah.com हरिद्वार, शुक्रवार, 30 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने युवाओं के कौशल विकास पर दिया विशेष जोर

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत आम जनता को योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि पात्र लोग समय पर उनका लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने और स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का समय पर एवं पूर्ण लाभ मिले और आवंटित बजट का प्रभावी आउटकम सामने आए। साथ ही उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त उन्नति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए। सेब की अतिसघन बागवानी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे प्रभावी ढंग से लागू कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के देयकों का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने और उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य करने को भी कहा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। हनी मिशन के अंतर्गत शहद उत्पादन को बढ़ावा देने, आर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने तथा बागवानी और मौन पालन में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ टीम भेजने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जबकि 25 अन्य उत्पादों को इस वर्ष चिन्हित किया जाएगा। स्टेट मिलेट पॉलिसी के तहत हजारों किसानों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं योजना 2.0 के अंतर्गत चार वर्षों में लक्ष्य से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। पर्यटन एवं मत्स्य पालन योजनाओं से भी हजारों लोगों को रोजगार मिला है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, वी. षणमुगम, धीराज गर्ब्याल सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

व्यवधान नहीं बल्कि समाधान के साथ आगे बढ़ने का समय : मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से संसद का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा है कि आज समय व्यवधान का नहीं बल्कि समाधान का है और देश के विकास में लाभकारी परिणाम देने के लिए सभी को इस समय का उपयोग करना चाहिये।

मोदी ने संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले यहां संसद भवन परिसर में गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह समय कार्यों में बाधा डालने का नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान का है।

उन्होंने कहा 'इस समय हमारी प्राथमिकता व्यवधान नहीं बल्कि समाधान है। यह हिम्मत ,समाधान और निर्णय का समय है इसलिए सभी सांसदों को राष्ट्र के लिये आवश्यक समाधानों को गति देने की दिशा में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा ताकि उनके निर्णयों के लाभकारी परिणाम देश को प्राप्त हो सकें। मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के कल

संसद के संयुक्त सत्र में दिये गये अभिभाषण का जिक्र करते हुए कहा 'राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति, उसका लेखा जोखा और खासकर युवाओं की अभिव्यक्ति को रेखांकित करने वाला था। यह बहुत ही सटीक अभिभाषण था और इसमें कई मार्गदर्शक बातें राष्ट्रपति जी ने कल सदन के सामने रखी। सत्र के आरंभ में और 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति ने सभी सांसदों से जो अपील की वह एक राष्ट्र की मुखिया के रूप में उनकी भावना की अभिव्यक्ति थी और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। यह महत्वपूर्ण सत्र है और देश के विकास के महत्वपूर्ण अगले 25 वर्ष का दौर शुरू हो चुका है। यह इस दौर का बजट है। '

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री हैं, महिला वित्तमंत्री हैं, जो लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही है। यह खुद में एक गौरव का पल है और भारतीय संसदीय इतिहास में इस पल को लिखा जा रहा है। उनका कहना था कि भारत आज विश्व के लिए आशा की किरण, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ हुये समझौते का उल्लेख करते हुए कहा 'दूसरे 25 साल की शुरुआत में ही यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हुआ है वह देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की झलक है। मैं सभी उत्पादकों से आग्रह करूंगा कि जब भारत यूरोपीय संघ के बीच 'मदर ऑफ ऑल डील' हुई है तो मुझे उम्मीद है कि देश के उद्योगों, विनिर्माण क्षेत्र के लिए अब बड़ा बाजार खुल गया है। उनका सामान बड़े बाजार में पहुंचने का यह अवसर है। अब बाजार खुल गया है तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का सामान हमें बाजार में पेश करना है और यूरोपीय संघ के देशों के खरीदारों का दिल जीतना है और उनमें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रभाव देना है, जो उनके दिल में दशकों तक रहेगा और भारत के लिए नये गौरव का अवसर प्रदान करेगा। यूरोप के 27 देश के साथ हुआ यह समझौता देश के मछुआरों किसानों और सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। यह समझौता सब में एक तरह का आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा तैयार करेगा। '

मोदी ने कहा कि बजट पर देश का ध्यान स्वाभाविक है और सरकार का प्रयास परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफर का रहा है। अब हम उससे भी आगे निकल चुके हैं और सबको इसे गति देने में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना है।

उत्तराखंड की बड़ी उड़ान, एविएशन इकोसिस्टम में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय सम्मान

पथ प्रवाह, हैदराबाद।

हैदराबाद स्थित बेगमपेट एयरपोर्ट में 29 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित देश के प्रतिष्ठित एविएशन इवेंट ङ्खद्बठ्ठद्दह्यस् द्बठ्ठस्रद्ब 2026 में उत्तराखंड राज्य को 'क्चद्गह्यह्ल स्ह्लड्डह्लद्ग द्घश्ह्म क्कह्म्श्रद्वश्लद्बठ्ठद्द श्वद्ध ,1ष्ड्डह्लद्बश्ठ्ठ × श्वष्श्ह्यङ्घह्यह्लद्गद्व' के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई दूरदर्शी एविएशन नीतियों और प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम मानी जा रही है। यह प्रतिष्ठित सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान सचिव सचिन कुर्वे, अपर

सचिव आशीष चौहान, संजय टोलिया सहित एविएशन सेक्टर से जुड़े अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड की इस उपलब्धि ने राज्य को देश के अग्रणी एविएशन-अनुकूल राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ-साथ चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने में एविएशन सेक्टर का प्रभावी उपयोग किया है। केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवाओं का व्यापक विस्तार, हेलीपोर्ट और हेलीपैड का विकास, यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं में हवाई संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान बना है।

चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों और सीमित समय में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन की सुविधा मिली, जिसकी देशभर में सराहना हुई। इसके साथ ही सीमांत एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने, उड़ान योजना के अंतर्गत एयर स्ट्रिप्स के उन्नयन और हेली-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के प्रयासों को भी राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से सराहा गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान उत्तराखंड की जनता, राज्य सरकार की टीम और एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भविष्य में चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और तकनीक-संपन्न बनाने के साथ-साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी एविएशन और हेली-टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए पर्यटन, निवेश, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विकास में नए अवसरों के द्वार खोलेगी और उत्तराखंड की पहचान राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और मजबूत होगी।

जिले के वनवासी क्षेत्र भेजा जंगली में ग्लोबल गुरूकुलम की होगी स्थापना

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं रिटायर्ड आईएएस एन. पी. सिंह तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जी. आर. राणा की उपस्थिति में बालोद जिले के गुरूर विकासखंड अंतर्गत सुदूर आदिवासी ग्राम भेजा जंगली में तथागत ग्लोबल गुरुकुलम का विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। यह आयोजन जनजातीय विकास के उद्देश्य से जकवार फाउंडेशन और तथागत ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण शामिल हुए।

भूमि पूजन से पूर्व राजा राव बाबा और कंकालीन माता की पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए एन. पी. सिंह ने कहा कि इस गुरुकुलम की स्थापना का उद्देश्य समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासी और ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि जब तक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शहरों जैसी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा ही रहेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भेजा जंगली में स्थापित होने वाला यह विद्यालय शिक्षा के स्तर पर दिल्ली और अन्य बड़े शहरों के प्रतिष्ठित स्कूलों के समान होगा। यहां बच्चों को केवल अकादमिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों की भी शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुलम में निशुल्क शिक्षा के साथ-साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस, केंद्रीय बलों एवं सेना भर्ती की तैयारी, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तथा महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। एन. पी. सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस विद्यालय का निर्माण कार्य फरवरी माह से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकल्प व्यक्त किया कि जब राजा राव पठार में राजा राव की पूजा का आयोजन होगा, उसी समय गुरुकुलम का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राजा राव के आशीर्वाद से यहां पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश जैसे उच्च पदों तक पहुंचेंगे और तभी इस पहल को सफल माना जाएगा।

इस गुरुकुलम से भेजा जंगली सहित आसपास के 10 से 12 गांवों के आदिवासी और ग्रामीण बालक-बालिकाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। भूमि पूजन की इस ऐतिहासिक पहल से पूरे वनांचल क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच शीला यादव, पंच नागेश्वर सलाम, दिनेश यादव, बलराम गोटी स हित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

एक नजर

तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ स्वच्छ सुंदर जनपद बनाने की मुहिम ला रही रंग

पथ प्रवाह, हरिद्वार।तीर्थ नगरी हरिद्वार को साफ स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में सफाई अभियान पिछले 2 माह 12 दिन से निरंतर चलाया जा रहा है। शहर से लेकर गांव कस्बों तक चलाये जा रहे इस अभियान का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने अवगत कराया कि बीएचईएल टाउनशिप प्रशासन विभाग की टीम द्वारा सीएफएफपी चौराहा एवं खोखा मार्केट के सामने तथा 132 केवी सब स्टेशन के पास साफ सफाई की गई। नेचर फाउंडेशन की अध्यक्ष किरण भटनागर ने अवगत कराया है कि नगर निगम के सहयोग से रोड़ीबेलवाला क्षेत्रांतर्गत कांवड़ पटरी मार्ग पर सफाई अभियान चलाया गया। भारत स्काउट गाइड के मनोज सिरोही ने अवगत कराया है कि नाई सोता घाट क्षेत्रांतर्गत पर सफाई अभियान चलाया गया। खण्ड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर मथाना,गोरधनपुर एवं पहलादपुर क्षेत्रांतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान 08 कुंटल कूड़ा कचरा एकत्रित किया गया।जिसको उचित निस्तारण हेतु कम्पोस्ट सेंटर भेजा गया।

यूजीसी गाइडलाइंस पर पार्षद अमरदीप बोले यह शिक्षा सुधार नहीं, समाज को तोड़ने की साजिश

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार शिवालिक नगर पालिका के पार्षद अमरदीप ने यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) की नई गाइडलाइंस को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इन गाइडलाइंस को 'गलत, बेगुनियाद और बेहद खतरनाक' बताते हुए कहा कि यह कदम शिक्षा सुधार के नाम पर हिंदू समाज को बांटने का एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। उनका आरोप है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें और तथाकथित डीप स्टेट सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। पार्षद अमरदीप ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यूजीसी गाइडलाइंस का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कई विधायक और सांसद बिना पूरी जानकारी और गहन अध्ययन के इस विषय पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि यह मामला सीधे तौर पर छात्रों और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने वर्ष 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए सांप्रदायिकता विरोध विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस विधेयक का उस समय भाजपा ने संसद में पुरजोर विरोध किया था, मौजूदा गाइडलाइंस उसी सोच की अगली कड़ी प्रतीत होती हैं। सभासद अमरदीप ने आरोप लगाया कि इन गाइडलाइंस के तहत विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही छात्र को संदेह की नजर से देखा जाएगा और वह पहले से ही अपराधी मान लिया जाएगा। किसी भी आरोप की स्थिति में पुलिस की सीधी दखलअंदाजी और गिरफ्तारी तक की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने इसे न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था विशेष रूप से स्वर्ण समाज के बच्चों को निशाना बनाती है। अंत में उन्होंने दो टूक कहा कि इस फैसले का वे हर स्तर पर विरोध करते हैं।

ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने विद्यार्थियों को बढ़ते नशे के विरुद्ध किया जागरूक

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए ड्रग्स विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। वरिष्ठ ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती द्वारा निजी विद्यालय में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों को बताया गया कि नशा न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना देता हैड्रग्स इंस्पेक्टर ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि नशे की लत व्यक्ति की सोच, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपने आसपास किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। कार्यक्रम के दौरान नशे के प्रकार, उसके दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधानों एवं इससे बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। छात्रों ने भी जागरूकता कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। विद्यालय प्रशासन ने ड्रग्स विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

परिवहन और आबकारी विभाग ने चलाया अभियान, शराब पीकर वाहन चलाना जीवन के लिए घातक

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

रोड सेफ्टी माह के अंतर्गत परिवहन विभाग एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से जन-जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों से शराब पीकर वाहन न चलाने की अपील की गई।

सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी माह के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के तहत शहर के समस्त शराब विक्रय केंद्रों (वाइन शॉप्स) पर 'डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव / शराब पीकर वाहन न चलाएं' विषयक जागरूकता बैनर लगाए गए हैं। यह अभियान परिवहन विभाग एवं आबकारी विभाग के आपसी समन्वय से क्रियान्वित किया गया है।

इस अवसर पर एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है और यह मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गंभीर एवं दंडनीय अपराध है। रोड सेफ्टी माह के दौरान परिवहन विभाग का विशेष फोकस प्रवर्तन के साथ-साथ नागरिकों को व्यवहार परिवर्तन हेतु जागरूक करने पर है, ताकि दुर्घटनाओं में वास्तविक और स्थायी कमी लाई जा सके। एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। शराब सेवन के पश्चात वाहन चलाना न केवल स्वयं के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि अन्य निर्दोष सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। रोड सेफ्टी माह के अंतर्गत ऐसे अभियानों का उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदार यातायात संस्कृति विकसित करना है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिजोली ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा इस अभियान में पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है। शराब विक्रय स्थलों पर लगाए गए जागरूकता बैनरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया जा रहा है कि शराब सेवन के बाद वाहन चलाना अवैधानिक होने के साथ-साथ जीवन के लिए भी अत्यंत घातक है।

इस संयुक्त पहल के माध्यम से आम जनमानस से अपील की गई कि वे रोड सेफ्टी माह के संदेश को आत्मसात करें, शराब सेवन के उपरांत स्वयं वाहन न चलाएं, सुरक्षित वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करें तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें। परिवहन विभाग भविष्य में भी प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता के माध्यम से सुरक्षित यातायात के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दबंगों के अस्लाह लाइसेंस होंगे निरस्त, अपराधियों में दिखेगा कानून का खौफ

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार में असलाह दिखाकर कानून का माखौल उड़ाने वाले दबंगों के लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के सख्त निर्देशों ने बाद पुलिस दबंगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। एसएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'पुलिसिंग, पुलिसिंग की तरह होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का भय साफ नजर आए। '

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में दिसंबर 2025 में जनपद में घटित अपराधों एवं उनके अनावरण की समीक्षा हेतु मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई।

बैठक में दिसंबर माह के दौरान पंजीकृत अपराधों, लंबित विवेचनाओं तथा विभिन्न अभियानों की बिंदुवार समीक्षा की गई। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने 07 दिसंबर 2025 से मुख्यालय स्तर पर चलाए जा रहे गंभीर

अपराधों में गिरफ्तारी एवं कार्यवाही अभियान, कालनेमि अभियान, ऑपरेशन स्माइल, गैरजमानतीय अपराधों में लंबित अभियोग, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित प्रदर्शन, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई, वर्ष 2025 में दर्ज हत्या के मामलों का वर्गीकरण, एसआर केस, एमएसीटी, आई-रैड एवं हिट एंड रन मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर पर प्रचलित 46 बिंदुओं की अपराध समीक्षा भी की गई।

गोष्ठी के दौरान एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सभी फायर स्टेशनों को पूर्ण तैयारी दशा में रखने तथा प्रत्येक अग्निकांड के वास्तविक कारणों की जांच रिपोर्ट समय से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराध होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपराध से पहले ही आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने रंजिश के मामलों में थाना प्रभारियों को स्वयं निगरानी रखने, शांति व्यवस्था बिगड़ने से पूर्व ऐहतियाती कार्रवाई करने तथा उग्रता व दबंगई दिखाने वाले अस्लाह धारकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामलों में कोई घटना होती है तो दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कच्ची शराब के अवैध कारोबार को बड़ी मानवीय क्षति का कारण बताते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने इसकी तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने और आबकारी विभाग से समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए। बलवा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

आगामी हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार संचालन और परीक्षा केंद्रों के आसपास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बिना वैध दस्तावेजों के संचालित वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए आधुनिक उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर बल दिया गया।

बैठक में एसपी क्राइम/ट्रैफिक जितेन्द्र मेहरा, एसपी सिटी अभय सिंह, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, एसपी संचार विपिन कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर निशा यादव, क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर जितेन्द्र चौधरी सहित जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं कोतवाली/थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

अभिभावक की भूमिका में दिखे एसएसपी डोबाल, 36 पुलिसकर्मी 'मैन ऑफ द मंथ' से सम्मानित

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद प्रभारी होने के साथ-साथ मातहतों के अभिभावक की भूमिका निभाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने 29 जनवरी 2026 को पुलिस कार्यालय रोशनाबाद स्थित सभागार में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में एसएसपी डोबाल का संवेदनशील और मानवीय पक्ष सामने आया, जहां उन्होंने उपस्थित सभी जवानों से आत्मीय संवाद स्थापित करते हुए उनकी कुशल-क्षेम जानी और व्यक्तिगत व विभागीय समस्याओं की जानकारी ली।

सम्मेलन के दौरान एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने जवानों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अपने स्तर से निस्तारण योग्य मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि अन्य उच्च स्तर की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जवानों का मनोबल ही मजबूत पुलिसिंग की रीढ़ है और उनकी समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सैनिक सम्मेलन के समापन अवसर पर एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ड्यूटी के दौरान अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए जटिल अपराधों के अनावरण,

जनसेवा तथा कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुल 36 पुलिसकर्मियों को माह दिसंबर 2025 के 'पुलिस मैन ऑफ द मंथ' से सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए कर्मियों में 05 महिला पुलिस/होमगार्ड कर्मी भी सम्मिलित रहीं।

सम्मानित पुलिसकर्मियों की सूची इस प्रकार है–

कोतवाली नगर से कांस्टेबल राहुल धनिक, थाना श्यामपुर से कांस्टेबल विनीत कुमार, थाना कनखल से कांस्टेबल संजू सैनी, कोतवाली ज्वालापुर से होमगार्ड शायरा बानो, थाना बहादराबाद से महिला कांस्टेबल नेहा डुकलान, कोतवाली रानीपुर से कांस्टेबल दीप गौड़, थाना सिड़कुल से वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेन्द्र तोमर एवं हेड कांस्टेबल संजय तोमर, कोतवाली रुड़की से कांस्टेबल गुलबहार, कोतवाली गंगनहर से महिला कांस्टेबल फुल्लो राय एवं होमगार्ड सुबोध चौधरी, थाना कलियर से अपर उप निरीक्षक सूरज नेगी एवं हेड कांस्टेबल सोनू कुमार, कोतवाली लक्सर से कांस्टेबल नवीन चन्द, थाना पथरी से अपर उप निरीक्षक मुकेश राणा, थाना खानपुर से कांस्टेबल त्रेपन सिंह, कोतवाली मंगलौर से अपर उप निरीक्षक ललिता एवं कांस्टेबल विनोद, थाना झबरेड़ा से उप निरीक्षक जय सिंह राणा, थाना भगवानपुर से कांस्टेबल अजय चन्देल, थाना बुग्गावाला से उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह, कार्यालय पुलिस अधीक्षक नगर से कांस्टेबल अरविन्द चौहान, कार्यालय क्षेत्राधिकारी मंगलौर से कांस्टेबल पंकज पाण्डेय, दूरसंचार शाखा से कांस्टेबल सन्तोष चौहान, फायर सर्विस रुड़की से फायरमैन सुनील सिंह,

पुलिस लाइन हरिद्वार से कांस्टेबल जय सिंह, आईआरबी प्रथम बी दल से कांस्टेबल पंकज मेहता, अभियोजन कार्यालय से कांस्टेबल जितेन्द्र रावत,

एएनटीएफ से उप निरीक्षक विक्रम सिंह बिष्ट, कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात से महिला कांस्टेबल किरण, सीपीयू हरिद्वार से कांस्टेबल अशोक कुमार, यातायात रुड़की से अपर उप निरीक्षक मनोज कुमार, पीसी-3 से कांस्टेबल शीशपाल राणा, एमसीयू से हेड कांस्टेबल अशोक कुमार तथा

नेफिस शाखा से कांस्टेबल दिगम्बर।

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने सभी सम्मानित जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और वे और अधिक निष्ठा व समर्पण के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उन्होंने अपेक्षा जताई कि सभी जवान इसी तरह अनुशासन, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते रहेंगे।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण ने दो अवैध निर्माण किए सील

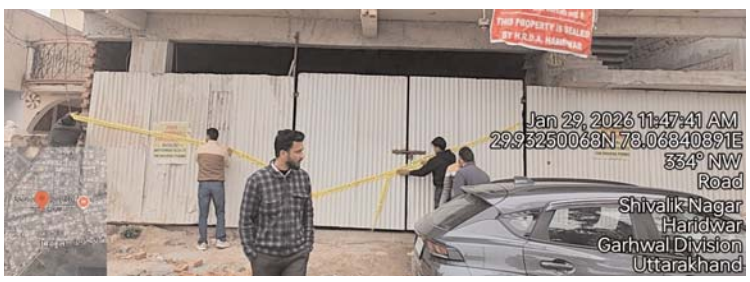

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

शहर में अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अवैध निर्माणों को मौके पर पहुंचकर सील कर दिया, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, शिवालिक नगर हरिद्वार फेज-2 में स्थित प्लॉट संख्या छ-224 पर आशु गुप्ता एवं रिजू गुप्ता द्वारा लगभग 30म60 फीट क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने स्थल का निरीक्षण करने के बाद निर्माण को अनाधिकृत पाते हुए तत्काल उसे सील कर दिया। दूसरी कार्रवाई श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार के पुराना हरिद्वार रोड स्थित योग क्रिया आश्रम के बगल में की गई। साध्वी अर्चना द्वारा लगभग 25म50 फीट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त निर्माण को भी सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थल पर उपस्थित अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जब तक हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण से विधिवत मानचित्र स्वीकृत नहीं करा लिया जाता, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आगे न किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के भाई पर गोली चलाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान के छोटे भाई पर गोली चलाकर प्राणघातक हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा जारी है। घटना कनखल थाना क्षेत्र अंतर्गत उषा टाउनशिप के बाहर की है। हालांकि इस सनसनीखेज मामले में एक आरोपी ने स्वयं थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल के निर्देशों पर प्रकरण में सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश एवं विवेचनात्मक कार्यवाही लगातार जारी है।

28 जनवरी 2026 को शिकायतकर्ता अमित कुमार, निवासी पंजनहेड़ी, कनखल ने थाना कनखल में तहरीर दी गई थी। शिकायत में बताया गया कि अतुल चौहान सहित कुल 06 आरोपियों ने वादी के भाई सचिन चौहान एवं कृष्णपाल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। इस घटना में सचिन चौहान के पेट तथा कृष्णपाल के हाथ में गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के संबंध में थाना कनखल पर

मु0अ0सं0 31/2026, धारा 109 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

इसी क्रम में 28 जनवरी 2026 को आरोपी अतुल चौहान ने थाना कनखल पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोपी ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी पुलिस के समक्ष दाखिल की गई है। पुलिस ने आरोपी को नियमानुसार हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि घटना में संलिप्त अन्य नामजद एवं अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

विवरण आरोपीः अतुल चौहान, पुत्र सुखवीर सिंह निवासी नूरपुर पंजनहेड़ी, कनखल हरिद्वार

संपादकीय

व्यावसायिक शिक्षा से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता राज्य

उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य संवारने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निस्संदेह दूरदर्शी और समय की मांग के अनुरूप है। समग्र शिक्षा एवं पीएम-श्री योजना के अंतर्गत प्रदेश के 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन को भारत सरकार से स्वीकृति मिलना, शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की उस मूल भावना को मजबूती देती है, जिसमें शिक्षा को रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

लंबे समय से यह महसूस किया जाता रहा है कि पारंपरिक शिक्षा विद्यार्थियों को डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार के लिए आवश्यक कौशल नहीं। इसी कमी को दूर करने के उद्देश्य से विद्यालय स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में शामिल किया गया है। एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, आईटी, प्लम्बिंग, रिटेल तथा टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी जैसे 8 प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर छात्रों को व्यावहारिक दक्षता प्रदान की जाएगी।

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में पलायन एक गंभीर चुनौती रही है। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न मिलने के कारण उन्हें अन्य राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है। व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार इस समस्या के समाधान की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। इससे न केवल छात्र रोजगार योग्य बनेंगे, बल्कि स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एनएसक्यूएफ के तहत मिलने वाले लेवल-3 और लेवल-4 के प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएंगे।

प्रदेश में पहले से संचालित 531 विद्यालयों में 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों का व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा होना और 146 छात्रों का कैम्पस प्लेसमेंट प्राप्त करना इस योजना की सफलता को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त एयरोस्पेस एंड एविएशन तथा फूड इंडस्ट्री जैसे आधुनिक क्षेत्रों को पाठ्यक्रम में शामिल करना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति को आगे बढ़ा रही है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मंशा इस पूरी योजना की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। यदि इस योजना का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड कुशल, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर युवाओं का राज्य बनकर उभरेगा। निःसंदेह यह पहल उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में एक दूरदर्शी और निर्णायक कदम है।

पद्म भूषण और एक शांत सार्वजनिक जीवन 'भगत दा'

- जय प्रकाश पाण्डेय 'पहाड़ी'

उस दिन उत्तराखंड में कुछ घोषित नहीं हुआ, कुछ स्वीकार किया गया था। समाचार सूचना की तरह आया, लेकिन धीरे-धीरे अर्थ में बदलता चला गया। जब यह स्पष्ट हुआ कि किसी के भगत दा, किसी के बाऊजी, किसी के ताऊजी और किसी के भाईसाहब श्री भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो प्रतिक्रिया तालियों में नहीं फूटी। वह ठहराव में प्रकट हुई, एक ऐसी सामूहिक अनुभूति के रूप में, जिसमें समाज ने अपने भीतर चल रहे एक लंबे सार्वजनिक आचरण को पहचान लिया। यह सम्मान उत्तराखंड और भारत माँ के लाल को मिली उपलब्धि का उत्सव तो था ही साथ ही इस अवसर ने उस निरंतरता को रेखांकित किया, जो दशकों से बिना शोर के चलती रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, ये परिचय उस क्षण गौण हो गए। सामने आया वह व्यक्ति, जिसे उत्तराखंड ने हमेशा पदों से नहीं, व्यवहार आत्मीयता और कर्तव्यपरायणता से पहचाना है।

इस सम्मान की गूंज किसी एक केंद्र से नहीं उठी। वह चमोली के माणा गाँव, जहाँ हिमालय की ऊँचाइयाँ जीवन को सादा और कठोर दोनों बनाती हैं से लेकर तराई भाबर के समतल विस्तार तक लगभग एक ही स्वर में महसूस की गई। संदेश आए, फोन जुड़े, पर उनमें औपचारिक बधाइयों की भाषा कम और आत्मीय संबोधन अधिक था। यह ऐसा संवाद था, मानो लोग किसी सार्वजनिक उपलब्धि पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हों, बल्कि अपने ही किसी परिचित जीवन-पथ को छू भर रहे हों। यह किसी पद या उपाधि का उत्सव नहीं था। यह उस लंबे संबंध की पुनःस्वीकृति थी, जो समय, स्मृति और विश्वास से बनता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी समाज से अलग नहीं होता, बल्कि उसी के भीतर रचा-बसा रहता है।

भगत सिंह कोश्यारी जी के सार्वजनिक जीवन को किसी एक पद या पहचान के दायरे में सीमित करना कठिन है। उनका राजनीतिक अनुभव विभिन्न भूमिकाओं से होकर गुजरा। राज्य के ऊर्जा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, संसद के दोनों सदनों की सदस्यता से लेकर राज्यपाल जैसे संवैधानिक उत्तरदायित्व तक किंतु इन पदों की श्रृंखला कभी उनकी सार्वजनिक पहचान का केंद्र नहीं रही। उनकी प्रासंगिकता पदों से नहीं, उस निरंतर दृष्टि से बनी रही, जो सत्ता के पहले भी सक्रिय थी और सत्ता के बाद भी। वास्तव में, उनकी राजनीतिक समझ का निर्माण संवैधानिक पदों से कहीं पहले शुरू हो चुका था। छात्र जीवन में छात्रसंघ सचिव के रूप में और आगे चलकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में उनकी भूमिका ने उन्हें राजनीति के औपचारिक मंच से पहले ही संस्थागत सोच से जोड़ दिया। यहीं उन्होंने प्रतिनिधित्व के अर्थ, बहस की जिम्मेदारी और निर्णय की नैतिकता को केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अभ्यास के

रूप में समझा। यही प्रारंभिक संस्कार उनके पूरे सार्वजनिक जीवन में एक स्थायी आधार की तरह उपस्थित रहे।

औपचारिक पदों से दूरी बने हुए अब भगत सिंह कोश्यारी जी को लंबा समय हो चुका है, फिर भी उनका संपर्क समाज से शिथिल नहीं पड़ा। आज भी वे उत्तराखंड के उन इलाकों में पहुंचते हैं जहाँ जाना सुविधा का नहीं, संकल्प का प्रश्न होता है। दुर्गम बसावटें, कठिन पर्वतीय मार्ग और हिमालय की ऊँचाइयाँ। इन यात्राओं में न कोई कार्यक्रम-पत्र होता है, न औपचारिक स्वागत। वहाँ केवल बातचीत होती है सीधी, बिना मध्यस्थता के। मानो यह स्मरण कराना आवश्यक हो कि सार्वजनिक जीवन की निरंतरता पद से नहीं, संवेदना और सुनने की क्षमता से तय होती है। उनका निजी जीवन भी इसी सार्वजनिक अनुशासन का विस्तार रहा है। आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय किसी त्याग-प्रदर्शन की तरह नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि के चयन की तरह सामने आता है जहाँ व्यक्तिगत आकांक्षाएँ सामूहिक दायित्व के सामने स्वतः सीमित हो जाती हैं। हाल ही में देहदान का संकल्प लेकर उन्होंने इस दृष्टि को एक और शांत, पर निर्णायक बिंदु तक पहुंचाया। यह सार्वजनिक जीवन की वह विरल आचार संहिता है, जहाँ सेवा अवसर नहीं बनती, स्वभाव बन जाती है।

उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक भी थी। 'उत्तरांचल प्रदेश' नामक 28 पृष्ठों की पुस्तिका में उन्होंने पृथक राज्य की आवश्यकता को भावनात्मक आग्रह नहीं, बल्कि ऐतिहासिक संदर्भों और समकालीन यथार्थ के ठोस विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया। यही वैचारिक दृष्टि बाद में उनकी पुस्तक 'उत्तरांचल प्रदेशः संघर्ष और समाधान इतिहास और तथ्यों के आलोक में' में और अधिक परिपक्व रूप में सामने आई। इन रचनाओं के केंद्र में उत्तराखंड की वह संरचनात्मक पीड़ा थी, जिसे अक्सर विकास की सामान्य भाषा में अनदेखा कर दिया जाता है। वनों, जल, ऊर्जा और खनिज संपदा के निरंतर दोहन के बावजूद स्थानीय समाज तक उसका न्यायोचित प्रतिफल न पहुँचना; रोजगार के अवसरों की कमी; और अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, इन सबने पलायन को अस्थायी संकट नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन कीस्थायी सच्चाई बना दिया। उनका आग्रह स्पष्ट था कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था की संयुक्त समझ के बिना संभव नहीं है।

सड़क संपर्क और परिवहन लागत के प्रश्न पर उन्होंने जिस ठोस उदाहरण से असमानता को उजागर किया, वह आज भी प्रासंगिक है पिथौरागढ़ से टनकपुर की 151 किलोमीटर की यात्रा पर 50.50 रुपये, जबकि टनकपुर से दिल्ली की 260 किलोमीटर की दूरी मात्र 15 रुपये में। यह तुलना किसी अलंकार का प्रयोग नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर सीधा प्रश्न थी, जो कठिन भूगोल को सहारा देने के बजाय दंड में बदल देती है। ऊर्जा प्रशासन के क्षेत्र में भी उनका प्रश्न नैतिक था। अपार जलविद्युत क्षमता के बावजूद उत्तराखंड का ऊर्जा-वंचित बने रहना उन्हें नीति की विफलता प्रतीत होता था। जब हिमाचल प्रदेश समान भौगोलिक परिस्थितियों में ऊर्जा आत्मनिर्भर बन रहा था, तब उत्तराखंड को अपने संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार तक न मिलना उनके लिए यह शासन-नैतिकता का प्रश्न था। वन प्रशासन के संदर्भ में उनका विश्लेषण और भी तीखा था। अविभाजित उत्तर प्रदेश में जहाँ कुल भूमि का केवल 17 प्रतिशत वन क्षेत्र था, वहीं उस वन संपदा का लगभग 66 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड में स्थित था। इसके बावजूद यह प्राकृतिक संपन्नता अवसर में नहीं बदल सकी। इसी विरोधाभास को उन्होंने एक वाक्य में समेट दिया-

'प्रचुर वन संपदा, फिर भी अंतहीन विपन्नता

विधानसभा और संसद दोनों में उनकी भूमिका इसी दृष्टि से संचालित रही। वे घोषणाओं से अधिक प्रक्रियाओं पर, और अनुभव से अधिक सूचना पर जोर देते रहे। उनके लिए विकास का अर्थ योजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि संस्थाओं की कार्यक्षमता था। यही कारण है कि उनके प्रश्न अक्सर असहज होते थे क्योंकि वे सतह नहीं, संरचना को छूते थे। शायद उनके सार्वजनिक जीवन का सबसे शांत, किंतु सबसे अर्थगर्भित पक्ष वही है, जो औपचारिक सत्ता के अवसान के बाद सामने आता है। सत्ता के समाप्त होने के बाद भी उनकी यात्राएँ रुकी नहीं। दुर्गम बस्तियाँ, ऊँचाई पर बसे गाँव और बर्फ से ढके हिमालयी क्षेत्र वे आज भी उनकी सामाजिक उपस्थिति के भूगोल हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण, किसी बीते अध्याय पर लगाया गया अलंकरण नहीं लगता। वह एक राजनीतिक आचार-संहिता की स्वीकृति है, ऐसी आचार संहिता, जिसमें शोर से अधिक संयम, सुविधा से अधिक निरंतरता और तालियों से अधिक प्रश्नों को महत्व दिया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी का सार्वजनिक जीवन यह स्मरण कराता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों और कानूनों से नहीं चलता, बल्कि उन व्यक्तियों से जीवित रहता है, जो शांत स्वर में कठिन प्रश्न्न पूछते रहते हैं और समाज से अपना रिश्ता कभी ढीला नहीं पड़ने देते।

जय प्रकाश पांडेय 'पहाडी'
(लेखक उत्तराखंड स्थित स्वतंत्र लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा ओएनजीसी, देहरादून में प्रबंधक हैं)

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: आत्मनिर्भर भारत की विकास का नया अध्याय

विनोद कुमार सिंह

भारत की आर्थिक विकास यात्रा केवल आँकड़ों और बजट घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र की जीवंत कथा है जो निरंतर संघर्ष,नवाचार और आत्मविश्वास के सहारे वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को मजबूत करता जा रहा है।वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 इसी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है,जो न केवल देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।आर्थिक सर्वेक्षण किसी भी देश के लिए एक दर्पण की तरह होता है, जिसमें बीते वर्ष की उपलब्धियाँ, आर्थिक सुधारों की दिशा और आने वाले वर्षों की विकास रणनीति प्रतिबिंबित होती है।वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण भारत की उस परिवर्तनशील तस्वीर को सामने लाता है,जहाँ देश तेजी से विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते वर्षों में जिस प्रकार वैश्विक संकटों, महामारी के प्रभावों और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरताओं के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है,वह अपने आप में प्रेरणादायी है। सर्वेक्षण बताता है कि भारत अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बनता जा रहा है। देश की आर्थिक वृद्धि दर में निरंतर मजबूती देखी गई है।विनिर्माण, सेवा क्षेत्र,कृषि,डिजिटल अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढाँचे में हो रहे तीव्र निवेश ने भारत की विकास गति को नई ऊर्जा दी है। आर्थिक सर्वेक्षण यह संकेत देता है कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। इस सर्वेक्षण में सरकार की नीतियों और सुधारों का विशेष उल्लेख है, जिन्होंने निवेश वातावरण को अधिक अनुकूल बनाया है।'मेक इन इंडिया','आत्मनिर्भर भारत', 'डिजिटल इंडिया'और'स्टार्टअप इंडिया' .जैसी पहलों ने भारत को नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से वैश्विक मंदी और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भी मजबूत गति से आगे बढ़ रही है।वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 देश की आर्थिक प्रगति का विश्लेषण करता है और भविष्य के संभावित विकास मार्ग को स्पष्ट करता हैयह दस्तावेज़ न केवल आंकड़ों का संकलन है,बल्कि नीति निर्धारण और रणनीतिक सोच का मार्गदर्शक भी है।मैंने अपने इस आलेख में मुख्यतः जी डी पी विकास दर, प्रमुख आर्थिक सेक्टरों के योगदान और सतत विकास की चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है।भारत की जी डी पी विकास दर एक सकारात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करती है।सर्वेक्षण और सरकारी अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर करीब 7.4% रहने का अनुमान है,जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक गतिशीलता दर्शाता है।यह अनुमान सांख्यिकी मंत्रालय की प्रथम अग्रिम अनुमान रिपोर्ट से लिया गया है,जिसमें जी डी पी वृद्धि दर को 7.4% बताया गया है।इससे पहले कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 6.3% से 6.8% की रेंज का अनुमान जताया था,लेकिन वास्तविक आंकड़ों और आर्थिक गतिविधियों के आधार पर यह रफ्तार बढ़ी है।इस 7.4% वृद्धि दर का अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी बनी हुई है,खासकर जब अन्य उभरती और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है।यह वृद्धि घरेलू खपत, निवेश,विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती के कारण संभव हुई है।आर्थिक ढाँचे की दृष्टि से जी डी पी की कुल वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख सेक्टरों के आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण और सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट पर आधारित हैं। इनके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि केन्द्रित और संतुलित है, न कि केवल एक या दो क्षेत्रों तक सीमित।सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तंभ है।सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में सेवाओं का योगदान जी डी पी में सबसे ऊँचा रहा और यह क्षेत्र लगभग 9.9% की वृद्धि दर से आगे बढ़ा।इसमें वित्तीय सेवाएँ, रियल एस्टेट,पेशेवर सेवाएँ और प्रशासनिक सेवाएँ शामिल हैं। व्यापार,होटल,परिवहन और संचार जैसे सेवा क्षेत्रों ने भी 7.5% से अधिक वृद्धि दर दर्ज की।यह उच्च वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि भारत में घरेलू मांग मजबूत है और उपभोक्ता खर्च तथा डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के उपयोग में वृद्धि ने अर्थव्यवस्था की धुरी को और मजबूत किया है।डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक शक्ति का नया आधार बन चुकी है।

हिंसा के दौर में गांधी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता

योगेश कुमार गोयल

2 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी जीवन पर्यन्त देशवासियों के लिए आदर्श नायक बने रहे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया सुपरिचित है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक महात्मा गांधी का आज 78वां बलिदान दिवस है, जिनकी 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अहिंसा की राह पर चलते हुए भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया था। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने कई किताबें लिखी, जो हमें आज भी जीवन की नई राह दिखाती हैं क्योंकि उनके ये अनुभव, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं, जितने उस दौर में थे। सही मायनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के करोड़ों युवाओं के पथ प्रदर्शक हैं। उनके जीवन के तीन महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनमें पहला था सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। दूसरा, जाति-पाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना को बल देना। तीसरा, चरखा, जो आगे चलकर आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना गया।

गांधी जी प्रायः कहा करते थे कि प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है, जिसे आप दूसरों पर डालते हैं तो उसकी कुछ बूंदें आप पर भी गिरती हैं। वे कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। दूसरों की तरक्की में बाधा बनने वालों और नकारात्मक सोच वालों में सकारात्मकता का बीजारोपण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को ही अंधा बना देगी। लोगों को समय की महत्ता और समय के सही सदुपयोग के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति समय को बचाते हैं, वे धन को भी बचाते हैं और इस प्रकार बचाया गया धन भी कमाए गए धन के समान ही महत्वपूर्ण है। वह कहते थे कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, वह भले ही कम महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कुछ करें। लोगों को जीवन में हर दिन, हर पल कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हुए गांधी जी कहा करते थे कि आप ऐसे जिएं, जैसे आपको कल मरना है लेकिन सीखें ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। उनकी बातों का देशवासियों के दिलोदिमाग पर गहरा असर होता था। महात्मा गांधी के विचारों में ऐसी शक्ति थी कि विरोधी भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। ऐसे कई किस्से भी सामने आते हैं, जिससे उनकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता, सत्यनिष्ठा और शिष्टता की स्पष्ट झलक मिलती है। एक बार महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे। सरोजिनी नायडू के दाएं हाथ में चोट लगी थी। यह देखकर गांधी जी ने भी अपने बाएं हाथ में ही रैकेट पकड़ लिया। सरोजिनी नायडू का ध्यान जब इस ओर गया तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, 'आपको तो यह भी नहीं पता कि रैकेट कौनसे हाथ में पकड़ा जाता है?' इस पर बापू ने जवाब दिया, 'आपने भी तो अपने दाएं हाथ में चोट लगी होने के कारण बाएं हाथ में रैकेट पकड़ा हुआ है और मैं किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। अगर आप मजबूरी के कारण दाएं हाथ से रैकेट पकड़कर नहीं खेल सकती तो मैं अपने दाएं हाथ का फायदा क्यों उठाऊं?'

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 'लैब ऑन व्हील्स' का फ्लैग ऑफ

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से छात्र कौशल संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 'लैब ऑन व्हील्स (इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड)' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभिनव मोबाइल लैब प्रदेश के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) सहित अन्य उभरती तकनीकों में व्यावहारिक एवं हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि लैब ऑन व्हील्स छात्रों के लिए लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा को मजबूत करेगी और उन्हें

तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस मोबाइल लैब के माध्यम से विज्ञान विषयों के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड में समझने और सीखने का अवसर भी विद्यार्थियों को मिलेगा, जिससे उनकी अवधारणात्मक समझ और नवाचार क्षमता को नई दिशा मिलेगी।

इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के सहयोग से संचालित यह लैब ऑन व्हील्स आगामी पाँच वर्षों तक प्रदेश भर की शिक्षण संस्थाओं में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक करेगी, उन्हें आधुनिक तकनीकों पर आधारित प्रशिक्षण देगी तथा वैश्विक संभावनाओं से जोड़ेगी। यह पहल राज्य में हैंड्स-ऑन एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण की उपलब्धता में मौजूद कमी को काफी हद तक दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।

लैब में उपलब्ध आधुनिक उपकरणों एवं प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स का लाभ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र समान रूप से उठा सकेंगे। इससे छात्रों में कौशल विकास के साथ-साथ रोजगारपरक दक्षताओं का भी विकास होगा।

इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, विधायक प्रमोद नैनवाल, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र भसीन, डॉ. जयपाल सिंह चौहान, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा इंफोसिस के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एक नजर

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान से जनकल्याण को नई गति

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेशभर में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत विशेष कैम्पों का व्यापक स्तर पर सफल आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे आम जनता तक पहुंचाना है। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 20 विशेष कैम्प आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से 18,673 लोगों ने विभिन्न विभागों की सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया। अब तक राज्यभर में कुल 504 कैम्पों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 4,08,541 से अधिक नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है।

इन विशेष कैम्पों के माध्यम से आम जनता को एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

सरकार का यह प्रयास न केवल सेवाओं की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत कर रहा है। इन कैम्पों में राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम, पंचायत और अन्य विभागों की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का समयबद्ध और पूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कैम्पों की गुणवत्ता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

प्रदेश में लगातार आयोजित हो रहे ये विशेष कैम्प उत्तराखंड सरकार की सुशासन, सेवा और समर्पण की नीति को सशक्त रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं तथा आम जनता के बीच सरकार के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत कर रहे हैं।

कश्मीरी युवकों से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी हिरासत में

पथ प्रवाह, विकासनगर। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में 28 जनवरी 2026 को दुकान से सामान खरीदने के दौरान हुए विवाद के मामले में पुलिस ने त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है। घटना में कश्मीर निवासी दो युवकों का एक स्थानीय दुकानदार से कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। मारपीट के दौरान एक युवक के सिर में चोट आने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक छुट्टियों के दौरान कश्मीर से अपने पिता के पास आए थे, जो पौंटा साहिब में किराए पर रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में फेरी लगाने का कार्य करते हैं। युवक अपने पिता के साथ फेरी के कार्य में सहयोग कर रहे थे। इसी दौरान विकासनगर क्षेत्र में दुकान से सामान खरीदने को लेकर दुकानदार से विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार द्वारा गाली-गलौच एवं मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली विकासनगर में मु0अ0सं0- 26/26, धारा 117(2), 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया। घटना स्थल के निरीक्षण, उपलब्ध साक्ष्यों तथा पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर नामजद मुख्य अभियुक्त संजय यादव को हिरासत में लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की गहनता से विवेचना की जा रही है तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है।

चीनी वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर की खोज के लिए दुनिया का पहला क्वांटम नेटवर्क विकसित किया

हेफेई। चीन के वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर (अदृश्य पदार्थ) की खोज के लिए दुनिया का पहला क्वांटम सेंसर नेटवर्क विकसित किया है। यह नेटवर्क पूर्वी चीन के हेफेई और हांगझोउ शहरों में स्थित प्रयोगशालाओं को जोड़ता है, जिनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर से अधिक है। यह शोध प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर में गुरुवार को प्रकाशित हुआ। इस परियोजना का नेतृत्व यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के वैज्ञानिकों ने किया।

डार्क मैटर को ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ब्रह्मांड में मौजूद कुल पदार्थ का लगभग 26.8 प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर है। यह न तो दिखाई देता है और न ही रोशनी के साथ किसी तरह की प्रतिक्रिया करता है। इसकी मौजूदगी का अनुमान केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगाया जाता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने एक्सियन नामक काल्पनिक कणों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। माना जाता है कि यही कण डार्क मैटर का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी अंतरिक्ष में डार्क मैटर के ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है, तो एक्सियन कण परमाणुओं के नाभिक पर बहुत हल्का सा प्रभाव डाल सकते हैं। यह प्रभाव इतना क्षणिक और कमजोर होता है कि उसे पकड़ना बेहद कठिन है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने हेफेई और हांगझोउ में कुल पांच अत्याधुनिक क्वांटम सेंसर लगाए, जिन्हें एक साथ समन्वित किया गया। इस नेटवर्क की खासियत यह है कि किसी संकेत को तभी वास्तविक माना जाता है जब वह एक साथ कई स्थानों पर दर्ज हो।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवथा मजबूत, सरकारों को उद्यमी की तरह काम करने की जरूरत: आर्थिक सर्वेक्षण

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में गुरुवार को प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को वैश्विक अनिश्चितताओं के समुद्र में अपने दम पर मजबूती से आगे बढ़ते जहाज के रूप में दर्शाया गया है और अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.8-7.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष में वृद्धि सात प्रतिशत से ऊपर रहेगी जो इस माह के शुरू में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमान की तुलना में सावधानी भरा लगता है। एनएसओ ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक वृद्धि की इस गति को घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियादी ताकत और नीतिगत सुधारों पर आधारित और प्रेरित बताया गया है।

सर्वे में सुधारों पर बल दिया गया है। इसके लेखक और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि सुधारों के जरिये भारत की वृद्धि दर को तीन वर्ष में वार्षिक आठ प्रतिशत के स्तर तक ले जाया जा सकता है।

समीक्षा में कहा गया है कि अप्रैल 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर घोषित आयात शुल्क के मद्देनजर सरकार ने नीतिगत और आर्थिक सुधारों पर भी ध्यान दिया और अब भारत चालू वित्त वर्ष के लिए सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।

सर्वेक्षण में कहा गया है , 'वर्ष 2025 की विडंबना यह है कि दशकों में सबसे मजबूत भारत के व्यापक आर्थिक प्रदर्शन का एक ऐसी वैश्विक प्रणाली से टकराव हो गया है जिसमें अब (देशों की) मौद्रिक स्थिरता, पूंजी प्रवाह या रणनीतिक सुरक्षा के रूप में अच्छी व्यापक आर्थिक सफलता दर्ज करने वाले देशों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ' डॉ. नागेश्वरन ने अपने प्राक्कथन में कहा है, 'साल 2025 दुनिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, शायद कुछ उम्मीदों के साथ शुरू हुआ और दूसरी उम्मीदों के साथ खत्म हुआ। हालांकि, एक खास बात जो लगातार बनी रही, वह थी कि कोविड के बाद से लगातार दिख रहा भारत का मजबूत व्यापक आर्थिक प्रदर्शन बरकरार रहा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना में कहा है कि अनिश्चितता के इस दौर में 'उद्यमशीलता की नीति' करने की दिशा में बढ़ने और गहन बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी नीति हो कि अनिश्चितता के उभरने से पहले ही उससे निपटने की कार्रवाई की जा सके, जोखिम से बचने की बजाय उनके बीच सही दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता सृजित करे।

समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि मजबूत थी और अगली दो तिमाहियों में इसमें और सुधार हुआ। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में तेज से कटौती की और बैंकों के पास कर्ज के लिए नकदी की उपलब्धता बढ़ाई।

सरकार ने गत फरवरी में पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आय कर में महत्वपूर्ण छूट की घोषणा की। राजकोषीय घाटे को बजट में इससे पिछले वित्त वर्ष के जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के मुकाबले 4.8 प्रतिशत पर लाया गया और इस वर्ष इसे 4.4 प्रतिशत तक सीमित का करने का लक्ष्य रखा गया।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के 9.2 प्रतिशत से घटकर केंद्र का राजकोषीय घाटा आधे से भी कम हो रहा है। राजकोषीय मजबूती के आधार पर भारत को 2025 में तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया।

इसमें कहा गया है कि घरेलू मांग से आर्थिक विकास को निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। पहले अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय चालू वित्त वर्ष में बढ़कर जीडीपी के 61.5 प्रतिशत तक पहुंचा जो वर्ष 2011-12 से इसका उच्चतम स्तर है। यह 2022-23 में भी इसी स्तर पर था।

इसमें कहा गया है कि उपभोग की शक्ति आर्थिक वातावरण के लिए सहायक है और इसे निम्न मुद्रास्फीति, रोजगार की मजबूत स्थिति और क्रय शक्ति की वृद्धि से बल मिला है। कृषि के मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित स्थिर ग्रामीण उपभोग और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों युक्तिसंगत बनाने से शहरी उपभोग में निरंतर सुधार दिखा है।

सकल निर्धारित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 30 प्रतिशत रहने से वृद्धि को निरंतर बढ़ावा मिला है। जीएफसीएफ में 7.6 प्रतिशत विस्तारित के साथ पहली छमाही में होने के साथ निवेश मजबूत हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 7.1 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और अनुषंगी क्षेत्र की वृद्धि 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पहली छमाही में अनुकूल मानसून से सहायता मिली।

कृषि संबंधी सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) पहली छमाही में 3.6 प्रतिशत रहा जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 2.7 प्रतिशत से अधिक है लेकिन 4.5 प्रतिशत के दीर्घ अवधि के औसत से कम है।

अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न

बारामती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का गुरुवार को यहां विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोगों की उपस्थिति के बीच अजित पवार के बेटों पार्थ पवार और जय पवार ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। इस दौरान उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले तथा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सहित कई प्रमुख नेताओं ने अंतिम संस्कार में शिरकत की और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस शोकपूर्ण अवसर पर महाराष्ट्र भर से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता बारामती पहुंचे थे। अंतिम रस्मों के दौरान शमशान में 'अजित दादा अमर रहे' और 'अजित दादा परत या' (अजित दादा वापस आओ) जैसे भावुक नारे गूंजते रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकंपा) के अध्यक्ष अजित पवार का बुधवार सुबह उस समय निधन हो गया था, जब उन्हें और चार अन्य लोगों को ले जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया था। विमान में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में तीन दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। अजित पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने विभिन्न सरकारों के तहत छह बार इस पद को संभाला था।

दो सत्रों में होगी उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा, परीक्षा केंद्र के पास लागू रहेगी निषेधाज्ञा

पथ प्रवाह,हरिद्वार।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुशम चौहान ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी /सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा-2024, (केन्द्र कोड़ 101) परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार पर दिनांक 31 जनवरी, 2026 को दो सत्र में आयोजित होगी। प्रथम सत्र प्रातः 09:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक संपन्न करायी जायेगी।

उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है।

नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता–1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने सेवा और संवेदनशीलता के साथ मनाया जन्मदिन

पथ प्रवाह, कोटद्वार।

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने इस वर्ष भी अपना जन्मदिन सादगी, सेवा और सामाजिक सरोकारों के साथ मनाते हुए एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने जन्मदिन को पारंपरिक उत्सव के स्थान पर जनकल्याण, मानव सेवा और गौ सेवा को समर्पित कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशील सोच और प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से प्रदर्शित किया।

जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उदयरामपुर स्थित जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा संचालित 'दीदी की पाठशाला' के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने वहां अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए तथा उनके लिए बाल पुस्तकालय की व्यवस्था भी की। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व पर प्रेरित करते हुए अनुशासन, परिश्रम और संस्कारों को सफलता

की कुंजी बताया तथा संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक एवं शैक्षिक प्रयासों की सराहना की।

जन्मदिन के दिन प्रातः उन्होंने कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धबली बाबा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश की उन्नति, क्षेत्र की खुशहाली और जनता के कल्याण की कामना की। इसके पश्चात वे कुष्ठाश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने वहां निवासरत लोगों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें राशन सामग्री वितरित कर सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना ही सच्ची जनसेवा है। इसके

बाद विधानसभा अध्यक्ष शिवराजपुर स्थित आकृति गौशाला पहुंचीं, जहां उन्होंने गौ सेवा करते हुए गायों को चारा एवं गुड़ खिलाया। साथ ही गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों और सेवा कार्यों से जुड़े लोगों को राशन सामग्री वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो करुणा और संवेदना की भावना को सुदृढ़ करती है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उदयरामपुर स्थित श्री सिद्ध बाबा मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। वहीं दुर्गा माता मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर क्षेत्र में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण स्थापित किया गया। अपने संक्षिप्त संबोधन में ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि जनता का स्नेह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है तथा जन्मदिन जैसे अवसर पर सेवा कार्य करने से आत्मिक संतोष के साथ आगे और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं तथा उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की।

एक नजर

एसपी उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय ने यातायात कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।जनपद में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा यातायात कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों एवं पत्रावलियों की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यातायात कार्यालय के स्टोर रूम का भी गहन निरीक्षण किया गया। स्टोर में उपलब्ध ट्रैफिक उपकरणों को व्यवस्थित एवं पूर्णतः क्रियाशील दशा में रखने के निर्देश देते हुए कहा गया कि समय-समय पर उपकरणों की साफ-सफाई तथा उनकी कार्यक्षमता की जांच अनिवार्य रूप से की जाए। खराब एवं अक्रियाशील उपकरणों को शीघ्र रिप्लेस कराने के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, ताकि यातायात प्रबंधन में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने उत्तराखंड पुलिस एप एवं ऑनलाइन चालान प्रणाली की समीक्षा करते हुए सभी लंबित चालानों को निर्धारित समय अंतराल में निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभारी यातायात को निर्देशित किया कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष जोर देते हुए आमजन में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बर्फबारी वाले मार्गों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने, अत्यधिक पाला अथवा बर्फ की स्थिति में पर्यटकों एवं राहगीरों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी जनक सिंह पंवार, वाचक पुलिस अधीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक यातायात लक्ष्मण सिंह चुफाल, आशुलिपिक कैलाश शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अल्मोड़ा के लमगड़ा व स्याल्दे में लगे बहुउद्देशीय शिविर, 998 लोग हुए लाभान्वित

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद अल्मोड़ा के विकासखंड लमगड़ा एवं स्याल्दे में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान' के तहत बहुउद्देशीय शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना तथा केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुँचाना रहा।

विकासखंड लमगड़ा अंतर्गत न्याय पंचायत बकस्वाड़ में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, पिपली में आयोजित शिविर में सचिव, उत्तराखंड शासन डॉ. पंकज कुमार पांडे ने प्रतिभाग किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए तथा जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सचिव ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित इस शिविर में शासन द्वारा नामित 28 विभागों ने सहभागिता की, जिससे ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की जानकारी एवं लाभ प्राप्त हुआ। शिविर में लगभग 764 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान 92 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 57 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया। शिविर के माध्यम से 635 से अधिक लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। मुख्य विकास

अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने कहा कि जिन शिकायतों का मौके पर समाधान संभव नहीं हो सका है, उनके लिए अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आम जनता को समयबद्ध राहत मिल सके।

शिविर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, दर्जा राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार दिनेश आर्या, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा, उपजिलाधिकारी जैती सौम्या गर्त्याल, खंड विकास अधिकारी निवेदिता खुलबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

स्याल्दे के पैठाणा में भी दिखा प्रशासन का सक्रिय स्वरूप

इसी क्रम में विकासखंड स्याल्दे की न्याय पंचायत पैठाणा में भी बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनीं तथा योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभान्वित किया। इस शिविर में कुल 234 लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। साथ ही 20 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 12 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

शिविर में विधायक सल्ट महेश जीना एवं उपजिलाधिकारी याक्षी अरोड़ा ने स्वयं उपस्थित रहकर जनसमस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए।

दोनों शिविरों को मिलाकर कुल 998 लोग लाभान्वित हुए तथा 69 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत आयोजित इन शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन-प्रशासन की पहुँच मजबूत हुई है और आम जनता को सीधे राहत मिलती नजर आई है।

पढ़ाई से रोजगार की सीधी राह, 544 स्कूलों में शुरू होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम

पथ प्रवाह, देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप अब उत्तराखंड के 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। समग्र शिक्षा एवं पीएम-श्री योजना के तहत चयनित इन विद्यालयों को भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिससे वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही छात्र-छात्राओं को पारंपरिक विषयों के साथ-साथ व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा।

विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन विद्यालयों में 8 प्रमुख क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। इनमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, आईटी, प्लम्बिंग, रिटेल तथा टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी जैसे

रोजगारोन्मुख विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों को उत्तराखंड बोर्ड एवं सीबीएसई के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिससे छात्र-छात्राएं विद्यालय स्तर से ही कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले कक्षा-10 एवं 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत क्रमशः लेवल-3 एवं लेवल-4 के दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ-साथ रोजगार बाजार में भी पहचान और अवसर मिलेंगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए पीएसएससीआईवीई के मानकों के अनुरूप 548 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं तथा निर्धारित योग्यता के अनुसार अनुभवी प्रशिक्षकों की तैनाती की जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में 531 विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिनमें 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 28 हब्स एंड स्पोक विद्यालयों के माध्यम से भी व्यावसायिक शिक्षा को विस्तार दिया जा रहा है। विभाग द्वारा एयरोस्पेस एवं एविएशन तथा फूड इंडस्ट्री जैसे नए क्षेत्रों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

व्यावसायिक शिक्षा के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। कक्षा-12 के प्रथम बैच के विद्यार्थियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय जॉब फेयर में 146 छात्रों को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कैम्पस प्लेसमेंट प्रदान किया गया, जो इस योजना की सफलता को दर्शाता है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा के साथ रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार से प्रदेश का युवा वर्ग आत्मनिर्भर बनेगा और उत्तराखंड को कुशल मानव संसाधन के रूप में नई पहचान मिलेगी।

एक नजर

घूसखोरी करते चौकी इंचार्ज और सिपाही रंगे हाथ गिरफ्तार

पथ प्रवाह, वाराणसी। जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में कार्रवाई के नाम पर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए चौकी इंचार्ज और सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। विजिलेंस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। मामले में पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है। चौकी इंचार्ज दिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव द्विवेदी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक पीड़ित पक्ष ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि दहेज से जुड़े मामले में पुलिसकर्मी जांच और राहत दिलाने के नाम पर अवैध धन की मांग कर रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत वाराणसी में कार्रवाई की। जैसे ही एंटी करप्शन टीम मौके पर पहुंची, आरोप है कि चौकी इंचार्ज दिवाकर मिश्रा ने घबराहट में रिश्वत की रकम जमीन पर फेंक दी, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी (DCP) ने तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज दिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव द्विवेदी को निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई को आम जनता में सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

दुकानदार पर हमला करने वाला आरोपी दबोचा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद करते हुए पुलिस ने विधि कार्रवाई की है। कोतवाली मंगलौर पर वादिया निवासी मंगलौर द्वारा खुद के पिता पर अरुण कुमार पुत्र कल्लू कश्यप निवासी मोहल्ला मानक चौक द्वारा जान से मारने की नीयत से गले पर चाकू से वार करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिससे संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी हरिद्वार द्वारा प्रभारी निरीक्षक मंगलौर को निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के क्रम में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई जिसके फलस्वरुप आरोपी अरूण को मय घटना में प्रयुक्त चाकू के साथ पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

3 फरवरी हरिद्वार तहसील में आयोजित होगा तहसील दिवस

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में दिनांक 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लेखपाल कक्ष तहसील हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिसमें तहसील हरिद्वार क्षेत्रांतर्गत के आमजन की शिकायतो का मौके पर निस्तारण किया जायेगा। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्धारित तिथि/समय एवं स्थान पर स्वयं प्रतिभाग करे,जिससे कि तहसील दिवस में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा सके।

जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर उप जिलाधिकारी रुड़की अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में विकास खंड रूड़की के न्याय पंचायत बेलडा के पंचायत घर बेलडा में जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर आयोजन किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में 721 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा 2136 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 5784 लोगों ने प्रतिभाग किया।

इस बहुउद्देशीय शिविर में 62 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 45 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपाध्यक्ष, समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति (राज्यमंत्री स्तर) देशराज कर्णवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचाना है तथा उनकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित करना है।

अपर उप जिलाधिकारी रुड़की अनिल कुमार शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवसियो की समस्याओं का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश दिए और जिन शिकायतों का जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में निस्तारित नहीं हो पाया है उन शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना सुनाश्चित करे। इस अवसर पर ग्राम खंड विकास अधिकारी सुमन कोठियाल सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

भगवानपुर में लगे शिविर में मिला योजनाओं का लाभ

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में उप जिलाधिकारी भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में विकास खंड भगवानपुर के न्याय पंचायत चुड़ियाला मोहनपुर सीएमडी इंटर कॉलेज चुड़ियाला मोहनपुर में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार शिविर में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनों से 1525 क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया गया तथा विभिन्न विभागों के माध्यम से 375 लोगों को विभिन्न प्रमाण पत्र निर्गत किए गए,इस शिविर में 1975 लोगों द्वारा किया गया प्रतिभाग।

आयोजित शिविर ने क्षेत्रवासियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 79 समस्याएं दर्ज कराई गई,जिसमें 56 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया,शेष समस्याओं को त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रदेश भर। की सभी न्याय पंचायतों में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे है,जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करते हुए संचालित योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है।जिसका लाभ ग्रामीणों को उन्हीं के द्वार पर उपलब्ध हो रहा है। इस दौरान अतिथियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बहनों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी वितरण किए। सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका एवं कैलेंडर का भी आमजन मानस को वितरण किया गया। शिविर में दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, शोभाराम प्रजापति, श्यामवीर सैनी, अजीत चौधरी, जिला मंत्री मधुप त्यागी, मंडल अध्यक्ष संदीप रघुवंशी, मंडल अध्यक्ष विराट,उप प्रमुख प्रमोद,खंड विकास अधिकारी आलोक गार्गेय सहित समस्त ग्राम प्रधानगण, पंचायत सदस्यगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सार्वजिनक स्थानों पर इश्तहार चिपकाने वालों पर होगी कार्रवाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार में सार्वजनिक दीवारों और इमारतों पर छपे इश्तहार प्रशासन के स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। अब ऐसे इश्तेहार प्रशासन की नजर में आ गए हैं। जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित एक ओर जहां धर्मनगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार अभियान चलवा रहे हैं वहीं दूसरी ओर हाईवे और मुख्य चौक चौराहों पर दीवारों पर कमर्शियल और गुप्त रोगों के इश्तहार धर्मनगरी की सुंदरता को दाग लगाने का काम कर रहे हैं। लोग बिना परमिशन अवैध रूप से दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने विज्ञापन के इश्तेहार लगा रहे हैं। कई जगह दीवारों पर लिखे ये विज्ञापन शर्मिंदगी का कारण भी बनते हैं। जिला प्रशासन हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन शहर में हर तरफ ये विज्ञापन शहर की सुंदरता पर बट्टा लगा रहे है। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि ऐसे विज्ञापन लिखने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में उन्होंने निर्देश ?दिये हैं। एनएचएआई को भी निर्देश दिये गए हैं वह हाइवे पर ओवर ब्रिज या फ्लाई ओवर की दीवारों पर इस तरह के पोस्टर लगाने या वॉल पेंटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

रजत जयंती समारोहः पत्रकारिता की गरिमा, सत्यनिष्ठा और सामाजिक दायित्व पर हुआ मंथन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का रजत जयंती समारोह अत्यंत हर्षोल्लास, गरिमा एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। यूनियन की 25 वर्षों की संघर्षपूर्ण, समर्पित एवं प्रेरणादायी यात्रा को समर्पित इस समारोह में पत्रकारिता के मूल्यों, सामाजिक सरोकारों और भविष्य की दिशा पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।

समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं मां शारदा की स्तुति के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध कथावाचक रविदेव शास्त्री ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत शुक्ला ने किया। समारोह के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष संजय आर्य ने यूनियन के गठन से लेकर वर्तमान तक की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सदैव जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने सभी अतिथियों, पत्रकार साथियों और गणमान्य नागरिकों का स्वागत किया।

विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अरुण शर्मा ने अपने संबोधन में यूनियन के 25 वर्षों के संघर्ष, उपलब्धियों और पत्रकार हितों के लिए किए गए आंदोलनों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें सत्य, निष्पक्षता और सामाजिक प्रतिबद्धता सबसे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पत्रकारों से अपील की कि वे मानकों और मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्भीक और ईमानदार पत्रकारिता करें। साथ ही उन्होंने बताया कि यूनियन लगातार पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान के लिए संघर्षरत है।

मुख्य अतिथि विधायक आदेश चौहान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं और समाज को दिशा देने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यूनियन से जुड़े पत्रकारों की निष्पक्ष एवं सच्ची पत्रकारिता की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भाग लेने वाले पत्रकारों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उस दौर में पत्रकारों ने आंदोलन की आवाज को देशभर तक पहुंचाया। विधायक चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का गठन संभव हो पाया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में हो रहे विकास कार्यों की भी सराहना की। हरिद्वार की मेयर किरण जैसल ने समारोह में उपस्थित पत्रकारों को रजत जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना होते हैं और उनकी लेखनी समाज को जागरूक करने का कार्य करती है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एवं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु शंकर करौरी महादेव ने ऑडियो संदेश के माध्यम से यूनियन को 25 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं प्रेषित कीं और पत्रकारों की भूमिका की सराहना की। प्रेस क्लब अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने सभी अतिथियों, पत्रकारों एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह समारोह पत्रकारिता के मूल्यों को सशक्त करने वाला रहा।

अध्यक्षीय भाषण में रविदेव शास्त्री ने कहा कि बदलते समय में पत्रकारिता के सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने सदैव सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने पत्रकारों द्वारा समाज के लिए किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए यूनियन को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम में ये रहे मुख्य रूप से मौजूद

इस अवसर पर जगदीश लाल पाहवा, डॉ. विशाल गर्ग, विजयपाल बघेल ग्रीन मैन, नितिन गौतम, लोकेंद्र अंतवाल विजयपाल सिंह, प्रेस क्लब महामंत्री दीपक मिश्रा सहित शहर के अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं डॉ हिमांशु द्विवेदी, अमित कुमार गुप्ता, मनोज खन्ना, राजकुमार पाल, संजय शर्मा, गगनदीप गोस्वामी, महेश पारीक, ऋषि सचदेवा, विपिन शर्मा, संदीप गोयल, संजय संतोषी, संजय रावल, जगदीश प्रेमी, अनिरुद्ध भाटी, संजय चौहान, सुनील शेट्टी, नरेंद्र ढीला, गौरव चक्रपाणि, जगदीश देशप्रेमी, रामकुमार शर्मा, देवेश शर्मा, सुमित तिवारी, कुलदीप अग्रवाल, आशु शर्मा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

एक नजर

टायर की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उपनगरी ज्वालापुर में देर रात एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर तेज धमाके सुनायी दिये। देखते ही देखते दुकान से आग की बड़ी बड़ी लपटे निकलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने दुकान में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया। साथ ही वक्त रहते आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोका गया। आग लगने के कारण दुकान में रखा समान जल कर खाक हो गया। आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम को एक घंटे का समय लग गया।

अपराधियों पर उत्तरकाशी पुलिस का शिकंजा, मनेरी में खोली गई हिस्ट्रीशीट

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय के निर्देशों के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार के पर्यवेक्षण में मनेरी व धरासू थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक मनेरी प्रदीप सिंह तोमर द्वारा क्षेत्र के अभ्यस्त अपराधी रवीन्द्र सिंह राणा (50 वर्ष) निवासी कामर, भटवाड़ी की लगातार अवैध नशे के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने पर उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में मनेरी, उत्तरकाशी व मुनिकीरेती थानों में अवैध चरस तस्करी के मामले दर्ज हैं। वहीं प्रभारी निरीक्षक धरासू मनोज असवाल के नेतृत्व में धरासू पुलिस ने 28 जनवरी 2026 की रात्रि को रुकम सिंह व राजू लाल को 56 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब व 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई, यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा वाले नियम, 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

न्यायालय ने इन नियमों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके कई प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस नियम का समाज और शैक्षिणक परिसर पर विभाजनकारी प्रभाव पड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ इन नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ये याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं।

पीठ ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नोटिस का जवाब 19 मार्च तक देना है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि 2012 के पहले के यूजीसी नियम लागू रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को बिना किसी शिकायत निवारण तंत्र के न छोड़ा जाए।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से कई चिंताओं को उठाया, जिसमें कहा गया कि इसके प्रावधान अस्पष्ट हैं और उनके दुरुपयोग की संभावना है। याचिका में 'जाति-आधारित भेदभाव' की अलग परिभाषा की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया, जबकि 'भेदभाव' की सामान्य परिभाषा पहले से मौजूद है। इसमें रैगिंग पर प्रावधानों की पूरी तरह अनुपस्थिति की कड़ी आलोचना की गई।

न्यायालय ने चिंता प्रकट करते कहा कि ये नियम एकता को बढ़ावा देने के बजाय छात्रों को जाति के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पीठ ने सुझाव दिया कि नियमों पर प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए जो सामाजिक वास्तविकताओं और मूल्यों को समझते हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय तुरंत अंतिम आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है और इसके बजाय विशेषज्ञ से इस पर पुनर्विचार चाहता है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, 'एक ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें प्रतिष्ठित न्यायविद हों... ऐसे लोग जो सामाजिक मूल्यों और समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्हें समझते हों। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा और लोग कैसे व्यवहार करेंगे।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने नियम 3 (1) (सी) की ओर ध्यान दिलाया, जो 'जाति-आधारित भेदभाव' को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को मान्यता नहीं दी गई है। चूंकि नियम 3(1)(ई) पहले से ही 'भेदभाव' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, इसलिए जाति-आधारित भेदभाव के लिए एक अलग परिभाषा अनावश्यक है।

यह प्रावधान मानता है कि केवल कुछ समूहों को ही भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

श्री जैन ने अपने तर्क में कहा, 'जब नियम 3(1)(ई) पहले से मौजूद है, तो 3(1)(सी) की क्या ज़रूरत है?

एक अन्य वकील ने एक ऐसे परिदृश्य की ओर इशारा किया जहां एक सामान्य श्रेणी के नए छात्र को आरक्षित श्रेणी के एक सीनियर द्वारा रैगिंग का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में वर्तमान नियम ऐसे मामले के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करते हैं और यहां तक कि पीड़ित को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि ऐसे नियम जातिविहीन समाज की दिशा में हुई प्रगति को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, 'जातिविहीन समाज की ओर बढ़ने में हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम प्रतिगामी हो रहे हैं? '

न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता शिक्षण संस्थानों में झलकनी चाहिए। न्यायमूर्ति बागची ने पूछा, 'अगर 2012 के रेगुलेशन में व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण था, तो अब इसे प्रतिगामी क्यों होना चाहिए?

विदित हो कि 2026 के ये नियम रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी द्वारा 2019 में दायर एक जनहित याचिका के बाद बनाए गए थे, जिनकी कथित तौर पर अपने विश्वविद्यालयों में जाति-आधारित भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या से मौत हो गई थी।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com